(e) It is not possible to accurately compare the prices prevailing in the international and domestic markets on account of different varieties traded, variations in quality, and additional expenditure incurred in grading and packaging for exports.

उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता

1063. **श्री अजीत जोगी:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिए राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) अभी तक कितने आवेदनों को मंजूरी दी गई है;

(ग) सरकार द्वारा अन्य आवेदनों के तेजी से निपटान के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) अभी तक राज्य-वार जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) (ख) और (घ) उपभोक्ता कल्याण निधि 27 जनवरी, 1994 से आरंभ हुई। अब तक प्राप्त आवेदनों, छानबीन के बाद मंजूर किए गए प्रस्तावों तथा उनमें दी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा (22 नवम्बर, 1996 तक) संलग्न है। (नीचे देखिए) (ग) उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों को निपटाने के लिए 1.12. 1994 से नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में इस प्रकार के प्रस्तावों को मंजूर करने के विशिष्ट उद्देश्य से एक अलग अनुभाग बनाया गया है। प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं और उनमें दिशा निर्देशों के अनुसार अपेक्षित सूचना समाविष्ट नहीं होती है जिसके कारण अन्ततः उनके निपटान में विलम्ब होता है और नामंजूर कर दिए जाते हैं। सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में पाई जाने वाली त्रुटियों के बारे में संगठन/आवेदकों को काफी पहले सूचित कर दिया जाता है ताकि वे इन कमियों को दूर कर सकें। आवेदनों के निपटान की गति आवेदकों/संगठनों की तत्परता और उनके दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करती है।

विवरण

22 नवम्बर की स्थितिनुसार अब तक प्राप्त हुए आवेदनों, छानबीन के बाद नामंजूर किए गये प्रस्तावों तथा उनमें दी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त हुए प्रस्तावों की सं॰	मंजूर किए गए प्रस्तावों की सं॰	मंजूर की गई राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	347	36	23,99,925.00
2. असम	05	01	72,000.00
3. बिहार	152	11	5,17,550.00
4. चंडीगढ़	7	01	67,500.00
5. दिल्ली	66	21	40,39,250.00
6. गोवा	2	–	–
7. गुजरात	24	8	15,80,250.00
8. हरियाणा	24	2	2,47,500.00
9. हिमाचल प्रदेश	22	4	2,08,080.00
10. जम्मू व कश्मीर	02	2	90,000.00
11. कर्नाटक	55	9	9,33,720.00
12. केरल	63	6	4,05,955.00
13. मध्य प्रदेश	12	2	1,00,800.00

1	2	3	4
14. महाराष्ट्र	45	7	16,87,290.00
15. मणिपुर	4	–	–
16. मेघालय	2	1	22,500.00
17. मिजोरम	51	–	–
18. नागालैण्ड	1	–	–
19. उड़ीसा	93	17	17,40,370.00
20. पंजाब	9	–	–
21. राजस्थान	66	9	13,83,300.00
22. सिक्किम	2	–	–
23. तमिलनाडु	237	41	36,96,680.00
24. त्रिपुरा	02	–	–
25. उत्तर प्रदेश	257	32	16,27,580.00
26. पश्चिम बंगाल	24	2	2,18,600.00
27. पाण्डिचेरी	1	–	–
योग:	1575	212	2,10,38,850.00

Hawala Transactions in by Indian Exporters to Russia

1064. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the Hawala transactions being carried out by the Indian exporters to Russia;

(b) if so, the details of estimated loss to the exchequer ever since India arrived at an agreement with Russia to pay back its dues in dollars;

(c) details of representation received by the CBDT from Federation of India Exporters Organisations regarding involvement of top-20 exporters to Russia in such rampant manipulations and over-invoicing; and

(d) details of action taken against Indian exporters, nature of irregularities committed and estimates of tax evasion exporter-wise alongwith the present status of investigation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

World Bank's assistance to boost tea production

1065. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Government have sought any financial assistance from the World Bank to boost production of tea in the country;

(b) if so, the amount sought for the purpose; and

(c) the response of the World Bank thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) A proposal for financial assistance to the tune of Rs. 2216.5 crore for development of tea industry in India has been submitted to the World Bank.

(c) A four member study team from the World Bank visited India during May/June, 1996 to make an assessment of the problems/ bottlenecks faced by the tea industry in India. The study team, after discussions with different institutions and preliminary data analysis, had identified issues which are to be addressed as a part of the project. Pursuant to discussions